आत्मनिर्भर भारत एवं चुनौतियां

*नरेन्द्र कुमार

सारः—

कोरोना के कारण धीमी हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने व अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए केन्द्र सरकार ने मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया है मुख्य एजेंडा कोविड—19 के कारण आए वैश्विक आर्थिक संकट को कैसे भारत अवसर में बदल सकता है साथ ही इससे भारत आने वाले दिनों में एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य देश और उसके नागरिकों को हर तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा इको—सिस्टम बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा जो भारतीय कंपनियों को वैश्विक मंच पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होने की अनुमति देगा

मुख्य शब्दः— आत्मनिर्भर भारत, उज्जवला योजना, वोकल फॉर लोकल, कोरोना संकट, अर्थव्यवस्था

परिचयः— प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संकट के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड रूपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था इस पैकेज को "आत्मनिर्भर भारत अभियान" का नाम दिया गया है प्रधानमंत्री ने कोविड—19 महामारी से पहले तथा बाद की दुनिया के बारे में बात करते हुए कहा कि 21वीं सदी के भारत के सपनों को साकार करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता Self-Reliance की परिभाषा में बदलाव आया है आत्मनिर्भरता आत्म केंद्रित से अलग है भारत 'वसुधेव, कुटुंबकम' की संकल्पना में विश्वास करता है क्योंकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदना देता है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। नेहरूवादी युग के आत्मनिर्भरता मॉडल के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) में भारतीय आत्मनिर्भरता और एक वैश्विक दुनिया में उद्योग के लिए एक दृष्टिकोण लंबे समय से अधिक है।

आत्मनिर्भर भारत के लिए पहल

- पीएम मोदी ने देश की जीडीपी का 10 प्रतिशत यानी 20 लाख करोड रूपए के ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज की घोषणा की।
- पीएम मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर एक देश, एक कृषि बाजार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया।
- किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी मिली।

- आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन कर कृषि उपजों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया।
- गांव में ही श्रमिकों के हुनर की पहचान के लिए मैपिंग की शुरूआत की गई
- GeM पर नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय उत्पादक देश की जानकारी देना अनिवार्य किया गया।
- घरेलू कंपनियों को अवसर देने के लिए 200 करोड रूपए तक की खरीद के लिए वैश्विक टेंडर पर रोक लगाई गई।

आत्मनिर्भरता भारत अभियान के पांच स्तंभ

1. अर्थव्यवस्था – एक ऐसी इकोनामी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, बल्कि क्वांटम जंप लाए।
2. बुनियादी ढांचा– एक ऐसा बुनियादी ढांचा जो आधुनिक भारत की पहचान बने 1 विदेशी कंपनियों को आकर्षित करें।
3. सिस्टम– एक ऐसा सिस्टम जिसमें आधुनिक तकनीक को अपनाने और समाज में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढाना शामिल है।
4. डेमोग्राफी– हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्त्रोत है।
5. मांग– हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और डिमांड क्षेत्र है उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है।

आत्मनिर्भरता खत्म करेगी निर्धनता

- पीएम मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर 2020 के अंत तक विस्तार करने की घोषणा की।
- 80 करोड से अधिक लोगों को नवंबर तक मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा।
- कोराना संकट के समय 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में 31,000 करोड रूपए स्थानांतरित किए गए।
- 3 महीने तक महिला जनधन खाता धारकों को प्रतिमाह रू. 500 दिए गए।
- गरीब बुजुर्ग, माताओं–बहनों और दिव्यांगों के लिए रू. 1000 की सहायता भी सीधे उनके खाते में भेजी गई।
- एक देश एक राशन कार्ड, योजना के तहत एक ही राशन कार्ड से किसी भी शहर या राज्य में राशन मिल सकता है।

आत्मनिर्भर किसान, समृद्ध भारत

आत्मनिर्भर भारत अभियान में मोदी सरकार ने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हाथ में अधिक पैसे पहुंचाने की कोशिश की है सरकार ने मार्च और अप्रैल के बीच 86600 करोड रूपए के 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र में दिए गए हैं इसके साथ ही सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की रिफाइनैसिंग के लिए नाबार्ड ने 29,500 करोड रूपए दिए है इसके साथ ही राज्यों को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फड के लिए 4200 करोड रूप्ए की मदद की गई ह

शहरी गरीब बनेंगे आत्मनिर्भर

भारत सरकार ने बताया है कि पिछले 2 महीने के दौरान प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब लोगों के लिए कई उपाया किए गए हैं जिससे उन्हें कोराना के बाद के दौर में जीने में आसानी हो इसमें प्रवासी मजदूर के रहने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के रकम के उपयोग की इजाजत दी गई है जिससे कि उनके लिए खाने और पानी की व्यवस्था की जा सके । केन्द्र सरकार ने राज्यों को 11,000 करोड रूपए दिए हैं जिससे की वह स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की मदद से इनके लिए काम कर सकें। अर्बन होमलेस शेल्टर में रहने वाले लोगों के लिए दिन में तीन बार खाने की व्यवस्था की गई है 12 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप में 3 करोड मास्क और सवा लाख सैनिटाइजर बनाए है इसके माध्यम से भी शहरी गरीबों को काम उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌योगों को बढावा

सरकार ने एमएसएमई को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इसकी परिभाषा में संशोधन किया है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार लघु उद्‌योग, लघु ही बने रहना चाहते हैं क्योंकि इससे इन उद्‌योगों को अनेक लाभ मिलते है।

सूक्ष्म या माइक्रो इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा एक करोड रूपए और टनओवर 5 करोड रूपए होना चाहिए।

छोटी इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 10 करोड रूपए और टर्न ओवर 50 करोड रूपए होना चाहिए।

मध्यम इकाई ने निवेश की ऊपरी सीमा 50 करोड और 250 करोड रूपए का टर्नओवर होना चाहिए।

संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए रू. 20000 करोड का प्रावधान किया गया इसमें दो लाख एमएसएमई को मदद मिलेगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ है 6 करोड से ज्यादा एमएसएमई जीडीपी में 29 प्रतिशत और निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत योगदान करते हैं इस क्षेत्र में 11 करोड में ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

वोकल फॉर लोकल

1 जुलाई 2020 तक 13.69 करोड लोगों ने आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड किया साथ ही देश की तकनीकी विशेषज्ञों ने इसे विश्व स्तरीय ऐप को बनाकर अपनी क्षमता प्रदर्शित की है।

कोविड अस्पतलों को मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति की गई।

कोविड अस्पतलों को मेड इन इंडिया वैटिलेटर की आपूर्ति की गई।

रक्षा मंत्रालय ने 26 सैन्य उपकरणों को केवल घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदने का फैसला किया है।

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (Gem) पर नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय उत्पत्ति देश की बारे में जानकारी देना अनिवार्य।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढावा देगा।

खादी और हैंडलूम की मांग रिकॉर्ड स्तर पर 6 साल में बिक्री में हुई जबरदस्त वृदधि निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है।

वित्त वर्ष	करोड रूपए
2013—14	1081
2014—15	1310
2015—16	1664
2016—17	2146
2017—18	2510
2018—19	3215
2019—20	4211.26

लोकल फॉर ग्लोबल

- पीपीई किट के मामले में आत्मनिर्भर बनने के बाद 50 यूनिट हर महीने निर्यात की मंजूरी दी गई है।
- देश में हर रोज 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं इसके निर्यात की कोशिश भी की जा रही है।
- खादी लोकल में ग्लोबल बनने जा रहा है खादी मास्क विदेशी बाजारों में दस्तक देने को तैयार है।
- केवीआईसी की योजना दुबई, अमेरिका, मॉरीशस, कई यूरोपीय और मध्य पूर्व के देशों में खादी फेस मास्क की आपूर्ति करने की तैयारी है।

आत्मनिर्भरता की आत्मा वसुधेव कुटुंबकम

- जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां आत्मनिर्भर भारत का संदेश लेकर पहुंचती हैं
- आत्मनिर्भरता विश्व से अलग—थलग नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन की कड़ी सफलता के लिए देश को तैयार करेगी।
- विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सचिवों का एक अंबार्ड ग्रुप बनाया गया है
- अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है।

- इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की सौगात है

आत्मनिर्भर भारत मिशन के सामने चुनौतियां

भारत को अपनी तकनीकी प्रौद्योगिकी क्षमता को बढाना होगा तथा साथ ही विभिन्न क्षेत्र जैसै बिजली और ईधन, सेल वाहनों, बिजली भंडारण प्रणालियों, शोर कोशिकाओं, और मॉड्यूल यूएवी, एआई, रोबोटिक्स, और संचालन बायोटेक फार्मा और अन्य सहित विमान में आत्मनिर्भर क्षमताओं को बढाना होगा तथा साथ ही शिक्षा पर भारत के अल्प सार्वजनिक व्यय को काफी हद तक कम करने की आवश्यकता है जिसमें कौशल विकास भी शामिल है किसी भी देश ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक शिक्षा के बिना आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है और कोई भी देश भारत में हमारे पास मौजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से ज्यादा मजबूत नहीं है भारत तथाकथित खाए हुए दशक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान, माइक्रोप्रोसेसर, पर्सनल कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, और विकेंद्रीकृत विनिर्माण और वैश्विक मूल्य श्रृखलाओं से युक्त तीसरी औद्योगिक क्रांति से पूरी तरह से चूक गया आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट फोन बाजार है हालांकि यह इनमें से किसी भी फोन को खुद नहीं बनाता है और महत्वाकांक्षी भविष्य के लक्ष्यों के साथ वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले सौर फोटोवोल्टिक कोशिकाओं और मॉड्यूल के केवल एक छोटे से अंश का निर्माण करता है सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत को स्वदेशी उत्पादों के निर्माण को बढावा देना होगा तथा बाहरी प्रौद्योगिकी के ऊपर निर्भर न रहते हुए स्वयं की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना होगा जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके

Conclusions

भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़े पैमाने पर ठोस प्रयासों की आवश्यकता होगी। क्योंकि आत्मनिर्भरता स्वयं नहीं होगी। पीएसयू और अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा बुनियादी अनुसंधान सहित राज्य वित्त पोषित अनुसधान एवं विकास को वर्तमान में जीडीपी के 1.1 प्रतिशत से काफी ऊपर होने की आवश्यकता है उन्नत और पुनर्निर्मित पीएसयू को भी पारिस्थितिकी में अपना विशिष्ट स्थान जाना महत्वपूर्ण होगा। निजी क्षेत्र के वितरण उन्मुख आरएंडी का भी समर्थन किया जा सकता है जो आपूर्ति श्रंखला के उचित स्तरों पर भी विनिर्माण में सार्थक भागीदारी से जुडा हुआ है। अंत में शिक्षा पर भारत अल्प सार्वजनिक व्यय में काफी हद तक वृद्धि करने की आवश्यकता है।

***शोधार्थी**
राजनीति विज्ञान
मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (उदयपुर)

सन्दर्भ सूची

1. Indian express 21, May
2. World Focus Magazine June, 2014
3. The Hindu Articles Based 27 May
4. Pib.gov.in 14 May
5. India Today Magazine

6. JE-Magazine July 2020
7. Kurushetra June 2019
8. E- Magazine July 2020
9. Indian Express
10. The Hindu Articles
11. World Focus Magazine June, 2020
12. Amar Ujala Articles 3 June
13. Indian Express
14. E-Magazine
15. Economics Times 20, May
16. The Hindu 8, July 2020